पाश की कविता

हमारे समयों में

यह सब कुछ हमारे ही समयों में होना था
कि समय ने रुक जाना था थके हुए युद्ध की तरह
और कच्ची दीवारों पर लटकते कैलेंडरों ने
प्रधानमंत्री की फ़ोटो बन कर रह जाना था

धूप से तिड़की हुई दीवारों के परखचों
और धुएं को तरसते चूल्हों ने
हमारे ही समयों का गीत बनना था

ग़रीब की बेटी की तरह बढ़ रहा
इस देश के सम्मान का पौधा
हमारे रोज घटते कद के कंधों पर ही उगना था
शानदार एटमी तजर्बे की मिट्टी
हमारी आत्मा में फैले हुए रेगिस्तान से उड़नी थी

मेरे–आपके दिलों की सड़क के मस्तक पर जमना था
रोटी मांगने आए अध्यापकों के मस्तक की नसों का लहू
दशहरे के मैदान में
गुम हुई सीता नहीं, बस तेल का टिन मांगते हुए
रावण हमारे ही बूढ़ों को बनना था
अपमान वक्त का हमारे ही समयों में होना था
हिटलर की बेटी ने ज़िंदगी के खेतों की मां बन कर
खुद हिटलर का 'डरौना'
हमारे ही मस्तकों में गड़ाना था

यह शर्मनाक हादसा हमारे ही साथ होना था
कि दुनिया के सबसे पवित्र शब्दों ने
बन जाना था सिंहासन की खड़ाऊं –
मार्क्स का सिंह–जैसा सिर
दिल्ली की भूल–भुलैयों में मिमियाता फिरता
हमें ही देखना था
मेरे यारो, यह कुफ्र हमारे ही समयों में होना था

बहुत दफा, पक्के पुलों पर
लड़ाइयां हुईं
लेकिन जुल्म की शमशीर के
घूंघट न मुड़ सके
मेरे यारो, अपने अकेले जीने की खाहिश कोई पीतल का छल्ला
है
हर पल जो घिस रहा
न इसने यार की निशानी बनना है
न मुश्किल वक्त में रकम बनना है

मेरे यारो, हमारे वक्त का एहसास
बस इतना ही न रह जाए
कि हम धीमे–धीमे मरने को ही
जीना समझ बैठे थे
कि समय हमारी घड़ियों से नहीं
हड्डियों के खुरने से मापे गए

यह गौरव हमारे ही समयों को मिलेगा
कि उन्होंने नफरत निथार ली
गुजरते गंदलाए समुद्रों से
कि उन्होंने बींध दिया पिलपिली मुहब्बत का तेंदुआ
और वह तैर कर जा पहुंचे
हुस्न की दहलीजों पर

यह गौरव हमारे ही समयों का होगा
यह गौरव हमारे ही समयों का होना है।

पेज 1 का शेष भाग

भ्रष्टाचार 'रोकेंगे' लेकिन स्रोत को जारी रखेंगे

इसके बावजूद प्रधानमंत्री के निर्देशन में थोड़ा-थोड़ा करके पूरे 70 हज़ार करोड़ लुटा दिये गये और अब जांच का नाटक कर रहे हैं। इसी तरह दूरसंचार मंत्री राजा करीब पौने दो लाख करोड़ रुपये डकार गया। यह लूट भी कोई अचानक या चोरी-छिपे नहीं हुई थी। लूट की यह प्रक्रिया भी बरसों तक चलने दी गयी। इसके विरोध में उठने वाली तमाम आवाज़ों को अनसुना कर दिया गया। शरद पवार के कृषि मंत्रालय से ले कर कोई भी मंत्रालय ऐसा नहीं है जिसमें बड़े पैमाने पर लूट न मची हो। क्या इन सबके लिए प्रधानमंत्री ज़िम्मेवार नहीं हैं? यदि वह नहीं हैं तो इस पद की जरूरत ही क्या है?

इसी तरह राज्यों में कौन-सा मूर्ख अथवा अनपढ़ आदमी ज़िले का डीसी लगेगा और कौन से एसपी को ज़िले के थाने पट्टे पर उठाने का ठेका दिया जायेगा, यह सब राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ही तय होता है। इसी तरह राज्य के मंत्री तथा विधायक भी अपनी-अपनी औकात एवं क्षमता के अनुसार राज्य के हर छोटे-बड़े सरकारी दफ़्तर को पट्टे पर उठा देते हैं। इसी सब के चलते देश की नस-नस में भ्रष्टाचार का संचार होने लगता है। आम जनता का कोई काम नहीं होता।

स्कूलों, कॉलेजों में शिक्षक नहीं तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं। सड़कों, नहरों, तथा इमारतों के निर्माण के लिए निकला सरकारी पैसा नेताओं, अफ़सरों व ठेकेदारों में बंट जाता है। भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर किये जा रहे तमाम नाटक भ्रष्टाचार की जड़ों में तो खाद-पानी लगाते हैं तथा उसके पत्तों व छोटी-मोटी टहनियों को तोड़ने की बात करते हैं। यदि भ्रष्टाचार रोकना है तो प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों समेत तमाम जजों को लोकपाल या किसी ऐसे तंत्र के घेरे में लाया जाये जो इनकी नकेल कस सके। इनके नीचे के स्तर के लोग़ों को पकड़ने का काम लोकपालों की बजाये खुद इनके ही कंधों पर डाला जाये, कोताही की स्थिति में इन पर ही कड़ी कार्यवाही हो। लेकिन यह सब इस मौजूदा व्यवस्था में होने वाला नहीं, क्योंकि सत्ता आज खुद चोरों और लुटेरों के हाथ में है।

विनायक सेन की रिहाई : कहां बची न्यायपालिका की साख?

क्या राजसत्ता पर काबिज़ एक वर्ग विशेष एवं उसके समर्थकों को ही देश की संज्ञा दी जा सकती है? नहीं, कदापि नहीं। देश कहलाता है वहां बसने वाली आम जनता से। जिस आम जनता की डॉ.सेन बरसों से सेवा करते आ रहे हैं, वही वास्तव में देश है न कि वहां के लुटेरे मुख्यमंत्री रमण सिंह व उनका गिरोह। ऐसे लुटेरे गिरोह की लूट का विरोध करना भला कैसे देशद्रोह ठहराया जा सकता है? डॉ.सेन की जमानत की अर्ज़ी को मंजूर करके जो सुप्रीम कोर्ट वाहवाही लूटना चाहती है, वह यह भी देखे कि अभी देश भर में डॉ.सेन जैसे न जाने कितने लोग़ इस तरह के तथाकथित अपराधों के लिए जेलों में सड़ रहे हैं। देशद्रोह की जो परिभाषा उच्चतम न्यायालय ने दी है, क्यों नहीं उसे देश भर की अदालतों में लागू करा कर, इस आरोप में बंदी लोग़ों को रिहा कराती?

डॉ.बिनायक सेन का यह मामाला न तो पहला है न तो आख़िरी। शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए बनी यह न्यायपालिका अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके उदाहरण के रूप में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में 1974 से 84 तक जज रहे श्री ए एस बैन्स पर किये गये अत्याचार को देखा जा सकता है। अप्रैल 1992 में चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी सुमेद सिंह सैनी ने उन्हें उस वक्त उठवा लिया था जब वे सुबह गोल्फ खेल कर अपने घर सेक्टर-2 की तरफ़ जा रहे थे। उन्हें उठाने के बाद सैनी ने पंजाब की रोपड़ पुलिस के हवाले कर दिया जिसने उनकी गिरफ़्तारी पंजाब के आनंदपुर साहिब से दिखा कर टाडा लगा दिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने भी उनकी जमानत लेने से इनकार कर दिया। उनका कसूर केवल इतना था कि जज रहते हुए उनके फ़ैसलों को कोई मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन आतंकवादी पुलिस कभी प्रभावित नहीं कर पायी थी। करीब साढ़े चार माह जेल में रहने के बाद तमाम दुनिया भर के मानवाधिकारवादी संगठनों द्वारा भारत सरकार की छीछालेदर किये जाने से जब खुद सरकार को ही शर्म आ गई और उसने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की। चार साल तक रोपड़ अदालत में चले उस झूठे मुकदमे में सरकार कुछ भी साबित नहीं कर पायी तो वे बरी हो गये। लेकिन जो साढ़े चार महीने वे अंदर रहे, उसका हिसाब पूछने वाला इस व्यवस्था में कोई नहीं है। इतनी 'न्यायप्रिय' एवं 'न्यायप्रदाता' है हमारी न्यायपालिका।

सड़े हुए सिस्टम को सुधारेंगे 'अमूल बेबी'?

स्टम सड़ा हुआ है, इस बात को अपने राहुल बाबा उर्फ़ अमूल बेबी भी मानते हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज वी आर कृष्णा अय्यर ने 9 अप्रैल को उन्हें जब एक कड़वा पत्र लिखा कि अन्ना को अनशन इसलिए करना पड़ा कि आप लोगों को सत्ता में बैठे भ्रष्ट लोगों पर हमला बोलना चाहिए, पर आप चुप और उदासीन हैं, तो राहुल बाबा ने जवाब दिया कि 'मैं भी सड़े सिस्टम को सुधारने में लगा हूं।' कृष्णा अय्यर ने राहुल बाबा को सलाह दी थी कि वे गांधी जी के सपनों वाला भारत, नेहरू जी की सोच वाला भारत बनाने में मदद करें, परमाणु संपन्न भारत बनाने में नहीं। वैसे हमें कृष्णा अय्यर से यह उम्मीद नहीं थी कि वे राहुल बाबा से यह उम्मीद लगा बैठे होंगे कि वे गांधी जी के सपनों का भारत बनाने का सपना देखते हों। हम तो अब तक यही समझते रहे हैं कि राहुल बाबा की रुचि देश का अगला प्रधानमंत्री बनने में हैं नहीं तो 'गैरराजनीतिक पोशाक' यानी जींस-टी-शर्ट पहन कर बढेरा के साथ पार्टियों में मस्ती करने में। राजमाता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद का त्याग कर अपने एक 'सेवक' को यह पद इसीलिए दिया था कि जब तक 'युवराज' राजनीति का ककहरा अच्छी तरह सीख नहीं लेते, तब तक वे पद को संभाले रखें। पर सरदार जी पद को ठीक से संभाल नहीं पाये। बड़े-बड़े घोटाले हो गये। घोटाले तो तब भी हुए थे जब 'युवराज' के पिता स्व. राजीव गांधी सत्ता में थे, पर अब अति हो गई और 'अति सर्वत्र वर्जयेत...।' इसलिए एक तरफ़ बाबा रामदेव खड़े हो गये ते दूसरी तरफ़ अन्ना अनशन पर उतारू हो गये।

यह बात सभी को मालूम है कि 'युवराज' जिन्हें हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री कामरेड अच्युतानंदन ने 'अमूल बेबी' कह कर संबोधित किया है, ग़रीबी और भ्रष्टाचार के मामले में बड़े ही संवेदनशील हैं। ग़रीबी की समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने कई रातें गांवों के ग़रीबों की झोंपड़ियों में बिताई है। यह एक नया तरीका इन्होंने अपनाया है। हमें विश्वास है कि ग़रीबों की झोंपड़ियों में रातें बिता कर और उनके यहां खा-पीकर ये ग़रीबी की समस्या का समाधान कर देंगे। रह गई समस्या भ्रष्टाचार की। इस संबंध में इनके पिता ने जो कहा था, उससे आगे बढ़ कर इन्होंने कहा है। पर हाल में हुए भ्रष्टाचार की बड़ी घटनाओं पर मुंह नहीं खोला है। इस समस्या का समाधान, लगता है ये तब करेंगे जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज़ हो जायेंगे। तब तक लोकपाल बिल आदि का तमाशा हो रहा है, ये तमाशा देख रहे हैं। लेकिन फ़िर भी राहुल बाबा को एक सलाह है। वे इस सिस्टम को सड़ा मत बतायें। सड़ी हुई चीज बेकार हो जाती है। उसे फेंकना पड़ता है। नहीं तो यह कहावत ग़लत नहीं है कि एक सड़ी मछली सारे जोहड़ को सड़ा देती है। दूसरी बात, इस गर्मी में सड़न बड़ी तेज़ी से फैलती है। सिस्टम का एक हिस्सा अगर सड़ जाता है तो देखते-देखते पूरे सिस्टम को सड़ा देता है। और राहुल बाबा यह भी जान लें कि सड़े हुए सिस्टम को सुधारा नहीं जा सकता, उस पर बैंडेज-पट्टी नहीं की जा सकती। उसका तो ऑपरेशन करना पड़ता है। तभी बात बनती है। अगर ऑपरेशन न करें और सोचे कि लोकपाल विधेयक आदि द्वारा बैंडेज-पट्टी कर काम चलाते रहेंगे तो लगातार मवाद बहता रहेगा दुर्गंध फैलती रहेगी। जनता नाक पर हाथ रख कर इस दुर्गंध को बर्दाश्त कर रही है। इसके सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं है। राहुल बाबा ने सही फ़र्माया कि सिस्टम सड़ा हुआ है, पर अभी जनता को इसी सड़े सिस्टम में रहना है। राहुल बाबा से सड़ा सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। दरअसल, यह सिस्टम अब इतना सड़ चुका है कि छोटा-मोटा ऑपरेशन कर के भी इसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। अब तो इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जाहिर है, यह काम राहुल बाबा नहीं कर सकते। वे प्रधानमंत्री पद के उत्तराधिकारी हैं। सड़े सिस्टम को सुधारने की बात कर सकते हैं। पर सवाल है कि जब सिस्टम सड़ गया तो इसे सुधारने की बात क्यों की जाये, नया सिस्टम लाने की बात क्यों न की जाये? नहीं। राहुल बाबा से ऐसी अपेक्षा न करें। वे इस सड़े सिस्टम को ही सुधारने में लगे रहेंगे जो कभी सुधरने वाला नहीं है। बहरहाल 'अमूल बेबी' ने तो इतना स्वीकार कर ही लिया कि सिस्टम सड़ा हुआ है, बड़े-बड़े खुर्राट नेता यह कभी स्वीकार न करें।

– ग़रीब दास

फरीदाबाद के पाठकों के लिए मजदूर मोर्चा अब हॉकरों के माध्यम से उपलब्ध है। जो भी हॉकर आपके यहां अखबार देने आता है, वह मांगने पर मज़दूर मोर्चा अवश्य देगा। डाक से अखबार पहुंचे या नहीं, इसका कोई ठिकाना न होने के कारण हमने यह नई व्यवस्था की है। अखबार मिलने में किसी तरह की समस्या होने पर हमारे प्रसार प्रबंधक से निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें :

दीक्षित न्यूज एजेंसी, 9811159238

सूचना : प्रिय पाठकों छपाई की बढ़ती लागत के चलते न चाहते हुए भी आपके इस समाचार पत्र की सहयोग राशि 2 रुपए की जा रही है। आशा है कि सहयोग बनाए रखेंगे।